Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2024 = 8.153
https://www.srjis.com/issues_data/234
Peer Reviewed & Refereed Journal, MAY-JUNE 2024, Vol- 13/83

बिहार में प्राथमिक शिक्षा: एक अवलोकन

संजू कुमारी सरोज

सहायक शिक्षिका, प्राथमिक विद्यालय परसा मथुरा, परसा, सारण, बिहार- 841219

Paper Received On: 20 May 2024

Peer Reviewed On: 24 June 2024

Published On: 01 July 2024

Abstract

प्रस्तुत शोध आलेख के माध्यम से बिहार में प्राथमिक शिक्षा प्रणाली के बारे में जांच की गयी है। शिक्षा सदियों से मानव विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्राथमिक शिक्षा एक बच्चे के जीवन की सबसे रचनात्मक अवधि होने के साथ विद्यालयी शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण चरण है। प्राथमिक शिक्षा प्रत्येक बच्चे का सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी अधिकार है। सभी बच्चों तक पहुंच सुनिश्चित करना न केवल सरकार का बल्कि माता-पिता का भी कर्तव्य है। प्राथमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों में जागरूकता लाना, आत्म-विकास के साथ-साथ अवसरों के रास्ते खोलना और अंतर-पीढ़ीगत गरीबी को कम करना है। यह कल्याण और समाज के निर्माण में पहला कदम है। प्राथमिक शिक्षा निरंतर विकास के लिए पूरी तरह से पूर्वापेक्षा है।

मुख्य शब्दः *प्राथमिक शिक्षा, बिहार, मूल अधिकार, सतत विकास.*

प्रस्तावना

बिहार में प्राथमिक शिक्षा को कक्षा एक से आठवीं तक की शिक्षा के रूप में परिभाषित किया गया है। मोटे तौर पर 5 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शामिल किया जाता है। प्राथमिक शिक्षा को आगे दो चरणों में विभाजित किया गया है: प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा कक्षा पांच तक चलती है और 5-11 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को शामिल करती है। उच्च प्राथमिक कक्षा कक्षा छः से आठ तक की कक्षाओं को शामिल करती है और इसमें 11-14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे शामिल होते हैं। हालांकि यह राष्ट्रीय और बिहार की तस्वीर है, लेकिन कुछ राज्यों में मामूली अंतर हैं। कुछ में केवल कक्षा चार तक की प्राथमिक स्कूली शिक्षा है, जबकि कुछ में केवल कक्षा सात तक उच्च प्राथमिक है। हालांकि, हमारे अध्ययन में, हमने 6-14 आयु वर्ग के बच्चों को शामिल करते हुए कक्षा एक से आठ तक प्राथमिक शिक्षा ली है। प्राथमिक शिक्षा कक्षा एक से पांच तक और उच्च प्राथमिक शिक्षा कक्षा छः से आठ तक क्रमशः 6-11 और 11-14 आयु वर्ग के बच्चों को शामिल करते हुए ली जाती है। वर्तमान अध्ययन मुख्य रूप से उन बच्चों तक सीमित है जो 5-14 वर्ष के आयु वर्ग में प्राथमिक स्कूल में जाते हैं अथवा नहीं जाते हैं।

बिहार राज्य का संक्षिप्त परिचय

2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार की आबादी 104 मिलियन है, जो इसे भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य बनाती है। बिहार की लगभग 88.7 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। बिहार में 0-6 वर्ष के आयु

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

वर्ग में 19.13 मिलियन बाल आबादी है, जो सभी भारतीय राज्यों में दूसरी सबसे बड़ी बाल आबादी है और इस आयु वर्ग में भारत की कुल बाल आबादी का 12 प्रतिशत है। बिहार की लगभग 46 प्रतिशत आबादी 18 साल से कम उम्र की है। बिहार भारत के सबसे गरीब राज्यों में से एक है, जिसमें लगभग 33.7 प्रतिशत आबादी गरीबी में रहती है। कृषि क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, जिस पर 90 प्रतिशत आबादी निर्भर है; हालांकि, राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में इसका योगदान केवल 20 प्रतिशत है। विकास के संदर्भ में खराब बुनियादी ढांचा एक बड़ी बाधा है। जातिगत समाज, सामंतवादी सामाजिक संरचना और जटिल सामाजिक स्तरीकरण के कारण राज्य में समानता की चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। यू.एन.डी.पी. के आंकड़ों के अनुसार, मानव विकास संकेतकों (एच.डी.आई.) के मामले में बिहार सबसे कम रैंकिंग वाले राज्यों में से एक है।

बिहार भारत के सबसे गरीब राज्यों में से एक है। यह देश का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और इसकी लगभग 46 प्रतिशत आबादी 18 साल से कम है। यह मानव विकास संकेतक के मामले में सबसे कम रैंकिंग वाले राज्यों में से एक है। इसकी कई चुनौतियों के बावजूद, हाल के वर्षों में बिहार में विकास में प्रगति हुई है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तरों पर नामांकन आंकड़ा अभी भी कम है। गांवों और छोटे शहरों में रहने वाले आम बच्चे, जो बिहार की आबादी का लगभग नब्बे प्रतिशत हिस्सा हैं, आमतौर पर सरकारी स्कूलों (सरकार द्वारा संचालित स्कूलों) में पढ़ते हैं।

इसकी कई चुनौतियों के बावजूद, हाल के वर्षों में बिहार में विकास में प्रगति हुई है। पिछले सात-आठ वर्षों में बेहतर शासन ने बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं, शिक्षा पर अधिक जोर, सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों के बेहतर प्रबंधन और अपराध और भ्रष्टाचार (राज्य सूचना / यूनिसेफ) में कमी आई है।

बिहार प्राथमिक शिक्षा परिदृश्य

प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने वाले सरकारी स्कूलों की अवस्थिति के संबंध में यह देखा गया कि बिहार में अधिकांश स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। इसका अर्थ है कि प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने वाले अधिकांश स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे हैं।

स्कूलों के श्रेणीवार वितरण से पता चलता है कि अधिकांश स्कूल स्वतंत्र प्राथमिक विद्यालय हैं। स्कूलों की संख्या में वृद्धि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों/वर्गों के अनुपात में भी परिलक्षित होती है, जो सर्व शिक्षा अभियान के प्रभाव को स्पष्ट रूप से दर्शाता है जिसके तहत हाल ही में बड़ी संख्या में स्कूल खोले गए हैं। हालांकि, बिहार में यह अनुपात काफी अधिक है यानी जिसके परिणामस्वरूप इसे अभी भी सुधारने की आवश्यकता है।

भवनों के प्रकारों के अनुसार स्कूलों के वितरण से पता चलता है कि अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों में पक्के (स्थायी) भवन हैं, जबकि कुछ स्कूलों में आंशिक रूप से पक्के और अन्य कुछ प्रतिशत में कच्चे (अस्थायी) भवन हैं। वास्तव में छोटे प्रतिशत में स्कूलें एक तम्बू में भी संचालित हो रहे हैं। सभी स्कूलों को पक्का स्कूल भवन उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाने चाहिए। निरपेक्ष दृष्टि से एकल कक्षा स्कूलों की संख्या महत्वपूर्ण है, जिसमें बिना देरी के सुधार की आवश्यकता है।

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

सुविधा संकेतक

स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता न केवल अधिक बच्चों को स्कूलों की ओर आकर्षित करती है बल्कि प्रतिधारण दर में सुधार करने में भी मदद करती है। वर्तमान में अधिकांश स्कूलों में पेयजल उपलब्ध है। पीने के पानी की सुविधा की तरह, अधिक स्कूलों में अब आम शौचालय और लड़कियों के लिए अलग शौचालय हैं। स्कूलों में कॉमन टॉयलेट के साथ-साथ लड़कियों के लिए अलग शौचालय है।

बिहार के स्कूलों के एक छोटे प्रतिशत में कंप्यूटर उपलब्ध है। स्वतंत्र उच्च प्राथमिक स्कूलों की तुलना में कंप्यूटर वाले प्राथमिक स्कूलों का प्रतिशत कम है। रैंप वाले स्कूलों के बढ़ती संख्या से विकलांग बच्चों को स्कूलों की ओर आकर्षित करने में मदद मिल सकती है। विकलांगता की प्रकृति द्वारा नामांकन के साथ, डी.आई.एस.ई. शायद एकमात्र स्रोत है जो स्कूलों में शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करता है।

मिड डे मील योजना के तहत सभी बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों में से एक है। अधिकांश स्कूलों में किचन शेड हैं।

बालक-बालिका समानता सूचकांक (जी.पी.आई.) और प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में बालिकाओं के नामांकन की प्रतिशतता से पता चलता है कि जी.पी.आई. और नामांकन में बालिकाओं की हिस्सेदारी दोनों में निरंतर सुधार हुआ है। बालिकाओं के नामांकन में सुधार कुल नामांकन में बालिकाओं के हिस्से में भी परिलक्षित होता है। प्राथमिक कक्षाओं में, लड़कियों के नामांकन का हिस्सा पिछले वर्षों की तुलना में बढ़ी है।

समय के साथ-साथ किए गए ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप अखिल भारतीय स्तर पर छात्र-कक्षा अनुपात में सुधार हुआ है। प्राथमिक विद्यालयों में एक कक्षा में औसतन लगभग 40 छात्र बैठते हैं। हालांकि, प्राथमिक स्कूलों के मामले में, बिहार में छात्र-कक्षा अनुपात अभी भी बहुत अधिक है। शिक्षकों की संख्या में वृद्धि छात्र-शिक्षक अनुपात में भी परिलक्षित होती है जिसने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों पर छात्र-शिक्षक अनुपात (अखिल भारतीय स्तर पर) में लगातार सुधार दर्शाया है।

स्कूलों की संख्या, स्कूलों में सुविधाओं और नामांकन में सुधार के साथ, स्कूल छोड़ने की दर में प्राथमिक स्तर पर औसत गिरावट देखने को मिलती है। हालांकि, ड्रॉपआउट के साथ बिहार प्राथमिक स्तर पर यूनिवर्सल रिटेंशन के लक्ष्य से बहुत दूर है।

शैक्षिक विकास सूचकांक

शैक्षिक विकास सूचकांक यू.ई.ई. की दिशा में प्रगति का मूल्यांकन करने के साथ-साथ प्रारंभिक शिक्षा पर निवेश के भावी पाठ्यक्रम का निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ई.डी.आई. के प्रमुख निष्कर्षों से पता चला है कि समग्र प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा के मामले में बिहार 35वें स्थान पर है, जो शीर्ष रैंक वाले राज्यों की तुलना में बहुत कम है। बिहार में ई.डी.आई. मान कम है जो प्राथमिक और समग्र प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों के लिए कुल मिलाकर (ऊपरी प्राथमिक को छोड़कर) सही है।

बिहार को अक्सर कला और सीखने के केंद्र के रूप में जाना जाता है और इसलिए बिहार में कई प्रसिद्ध स्कूल हैं जो सीखने की महत्वपूर्ण स्थानों के रूप में कार्य करते हैं। बिहार के स्कूल कला के संरक्षण के लिए जाने जाते हैं जिसने

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

कई कलाकारों की खोज में मदद की है और इस तरह देश को कई प्रतिभाशाली दिमाग दिए हैं। इन स्कूलों के छात्रों को निश्चित रूप से भारत के अन्य राज्यों में अपने समकक्षों पर बढ़त हासिल है।

बिहार में प्राथमिक शिक्षा प्रणाली

स्कूल व्यक्तियों की प्रणालियाँ और उप-प्रणालियाँ हैं जो सामूहिक रूप से स्कूली शिक्षा के व्यवसाय का संचालन करते हैं। कक्षाएं स्कूल से अलग संस्थाएं नहीं हैं; वे बड़े स्कूल संदर्भों से स्वतंत्र रूप से काम नहीं करते हैं क्योंकि स्कूल के अंदर और बाहर दोनों जगह कई कारक, किसी दिए गए स्कूल में कक्षा शिक्षण की गतिशीलता को प्रभावित कर सकते हैं।

शिक्षकों के काम का राजनीतिक संदर्भ

प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के काम के राजनीतिक संदर्भ को समझने के लिए, बिहार में संचालित उनकी रोजगार नीतियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, राज्य में संचालित प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की रोजगार नीतियों और उनके प्रशिक्षण कार्यक्रमों से संबंधित कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों से आँकड़े संग्रहित किए गए है।

शिक्षकों की रोजगार नीतियां

बिहार में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को अन्य विभागों के राज्य कर्मचारियों के बराबर नियमित सरकारी सेवा शर्तों पर भर्ती किया गया है। यह प्रथा लगभग अभी के वर्षों तक बनी रही, हालांकि हर साल भर्तियां नहीं की गईं और शिक्षकों की मांग बढ़ती रही हैं।

चयन के लिए मानदंड 'मेरिट' होता है। नियमित वेतनमान और सेवा शर्तों पर राज्य सरकार के कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किया जाता है।

'शिक्षा-मित्र योजना'

बिहार में पैरा-शिक्षकों की उत्पत्ति का पता राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2002 से शिक्षा मित्रों को नियुक्त करने की पहल से लगाया जा सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से नियमित वेतनमान पर शिक्षकों की भर्ती की पिछली प्रथाओं से स्पष्ट प्रस्थान करते हुए, 2002 की प्राथमिक शिक्षक रोजगार नीति, जिसे शिक्षा मित्र योजना के नाम से जाना जाता है, ने पंचायतों या नगरपालिकाओं द्वारा 11 महीने के अनुबंध पर प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति शुरू की। इन शिक्षकों को पंचायत शिक्षा मित्र (जब नियुक्ति पंचायत द्वारा की जाती थी) और नगर शिक्षा मित्र (जब नगरपालिकाओं द्वारा नियोजित किया जाता था) कहा जाता था, उन्हें 1500/- प्रति माह का निश्चित मानदेय दिया जाना था।

शिक्षक नियोजन

2005 में राजनीतिक नेतृत्व में बदलाव के बाद, बिहार की राज्य सरकार ने नियोजन आधार पर प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्तरों पर पढ़ाने के लिए लगभग 2.6 लाख शिक्षकों को नियुक्त करने का निर्णय लिया और शिक्षा मित्रों के रोजगार को अनुबंध पर रोक दिया। इस प्रकार, शिक्षा मित्र भर्ती योजना (2002-03) के कई पहलुओं में

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

2006 में काफी संशोधन किया गया क्योंकि रोजगार के मानदंडों और प्रक्रिया को निर्दिष्ट करने के लिए नियोजन नियम-2006 के रूप में संदर्भित रोजगार नियमों का एक स्पष्ट सेट तैयार किया गया था।

बिहार सरकार के अनुसार, नियोजित शिक्षक, "नियोजन नियमवाली-2006 के अनुसार और उसके बाद के क्रमिक रोजगार नियमों के तहत राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक हैं"। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रोजगार पर नई नियम पुस्तिका "नियोजन नियम-2006" का उपयोग करते हुए राज्य ने नियोजन आधार पर स्कूल शिक्षकों के रोजगार के लिए पहला बड़ा अभियान शुरू किया और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के एक बड़े हिस्से को प्राथमिक स्तर सहित स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर भर्ती किया गया।

निष्कर्ष

1970 के दशक से पहले बिहार के अधिकांश प्राथमिक विद्यालय समुदाय द्वारा चलाए जाते थे। इन स्कूलों का प्रबंधन उनकी अपनी प्रबंधन समितियों द्वारा किया जाता था। 1981 तक इन सभी स्कूलों को सार्वजनिक संस्थानों में बदल दिया गया और सरकार के प्रबंधन के अधीन कर दिया गया। नतीजतन, इन स्कूलों को धीरे-धीरे समुदाय से अलग कर दिया गया। बिहार में प्राथमिक विद्यालय नामांकन पिछले कुछ वर्षों में बड़े पैमाने पर विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों, जैसे- सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि के कारण बढ़ा है। प्राथमिक सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) के प्रतिशत बढने के साथ, यह स्पष्ट है कि स्कूली शिक्षा तक पहुंच की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इसे प्राप्त करने के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार प्राथमिकता रही है। निचले प्राथमिक स्तर पर लगभग सार्वभौमिक नामांकन प्राप्त करने के बाद, पांच साल की प्राथमिक स्कूली शिक्षा पूरी करने वाले बच्चों द्वारा प्राप्त सीखने के परिणामों के स्तर और इसके लिए जिम्मेदार कारकों पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है।

संदर्भ

बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006, बिहार का राजपत्र (असाधारण), पटना।

बिहार विद्यालय शिक्षा समिति अधिनियम (बिहार स्कूल एडुकेशन कमिटी ऐक्ट) 2000, पटना: ईस्टन बुक एजेंसी।

बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति अधिनियम (बिहार एलीमेंट्री एडुकेशन एडुकेशन कमिटी ऐक्ट) 2011, बिहार राजपत्र (असाधारण), पटना।

सिकदर, एस., और मुखर्जी, ए.एन. स्कूली शिक्षा में नामांकन और ड्रॉपआउट दर। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, XLVII (1), 27-31 /

बिहार सरकार (2007). न्याय के साथ विकास के दो साल, रिपोर्ट कार्ड।

कौल, आर. (2001). प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच: कक्षा से परे जाना। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, वॉल्यूम 36 (2): 155-162) /

कुमार, खगेन्द्र एवं कुमारी, किरण (2008). पंचायत: सत्ता और शिक्षा (हिन्दी), पटना: विशाल।

लाल, मनोहर। बिहार में सीतामढ़ी जिले के चयनित ब्लॉकों में प्राथमिक शिक्षा में ग्राम शिक्षा समिति (वीईसी) के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी। नई दिल्ली: एनयूईपीए।

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies